SKC-AKG/1C/2.00

The House reassembled at two of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, let us now proceed with the Motion of Thanks on the President's Address. Shri Amit Anil Chandra Shah to initiate the Motion.

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह (गुजरात) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि महामहिम राष्ट्रपति के प्रति निम्नलिखित रूप में कृतज्ञता ज्ञापित की जाए:-

> "राष्ट्रपति जी ने 29 जनवरी, 2018 को संसद की दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक में जो अभिभाषण दिया है, उसके लिए राज्य सभा के वर्तमान सत्र में उपस्थित सदस्य राष्ट्रपति के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।"

माननीय सभापति महोदय, आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है, क्योंकि आज इस महान और ऐतिहासिक सदन के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें मैं भी सम्मिलित होने जा रहा हूँ। आज मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और मैं गुजरात के विधान मंडल और गुजरात की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ चुन कर भेजा, तो मैं इस महान सदन के सदस्य के रूप में आप सबके बीच खड़ा हूँ।

माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को अगर हम ध्यान से देखें, तो उन्होंने बहुत सारी चीजों पर इस सरकार की उपलब्धियों को हम सबके सामने रखा है। इस पर आम तौर पर सदन के बाहर भी चर्चा होती है, इन उपलब्धियों पर अनेक प्रकार की टीका-टिप्पणियाँ होती हैं और कुछ मर्मज्ञ इसका विश्लेषण भी करते हैं। जब मैं उन विश्लेषणों को देखता हूँ, तब मुझे लगता है कि विश्लेषण का स्वागत जरूरी है, मगर मैं उसमें एक अलग दृष्टिकोण भी जोड़ना चाहता हूँ। महोदय, हमें यह देखना पड़ेगा कि अभी सरकार की ये जो उपलब्धियाँ हैं, इस सरकार को विरासत में क्या मिला, सरकार ने जब कामकाज सँभाला, तब सरकार के पास विरासत में क्या था। जिस प्रकार का गड्ढा था, वह गड्ढा भरने में ही सरकार का बहुत सारा समय गया है और गड्ढा भरने के बाद इन उपलब्धियों को हमें एक अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। ...(व्यवधान)... अब थोड़ा सुनिए न। हम आपको भी सुनेंगे।

MR. CHAIRMAN: Please no running commentary by anybody while sitting, either from this side or that side. It is for the first time that the Member is speaking. ...(Interruptions)... It is his maiden speech. I will have to name you. ...(Interruptions)... If anybody speaks while sitting and makes comments, that is a very serious matter, not just about this but about any issue. यह क्या स्वभाव है?

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह : सभापति महोदय, 2013 में देश की जो स्थिति थी, हमें उसको याद करना पड़ेगा। 2013 में देश की स्थिति क्या थी? देश एक ऐसे प्रश्न के

वक़ार के नीचे जी रहा था कि यह देश किस दिशा में जा रहा है, देश का भविष्य क्या होगा, यह महान देश अपनी विकास की गति को कहीं रोक तो नहीं देगा? इस प्रकार का एक भय था। यह वक़ार पूरे देश के जनमानस पर छाया हुआ था। महिलाएँ अपने आपको असुरक्षित महसूस करती थीं। सीमाओं की सुरक्षा का कोई ठौर-ठिकाना नहीं था। सीमा की रक्षा करने वाले जवान ...(व्यवधान)... सीमा की रक्षा करने वाले जवान सरकार की अनिर्णायकता के कारण अपने शौर्य का प्रदर्शन भी नहीं कर सकते थे। युवा आक्रोशित था। 12 लाख करोड़ रुपए के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, scams की एक series इस देश की जनता के मानस पटल पर बहुत बड़े सवाल कर रही थी। उसी वक्त एक सवाल खड़ा हुआ कि उस सरकार को policy paralysis हो गया है, नीतिगत मामलों में सरकार को लकवा लग गया है। पूरे देश ने मानो एक साथ निर्णय किया कि देश की परिस्थिति को बदलना चाहिए। इतने में ही 2014 में चुनाव आया और 2014 के चुनाव में इस देश की महान जनता ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया।

(1डी/एससीएच पर जारी)

SCH-HK/2.05/1D

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह (क्रमागत) : महोदय, तीस साल से इस देश में अस्थिरता चल रही थी और तीस साल से इस देश की जनता ने किसी भी एक दल को बहुमत नहीं दिया था। आज़ादी के बाद कभी भी इस देश की जनता ने किसी गैर-कांग्रेसी दल को बहुमत नहीं दिया था, लेकिन 2014 के चुनाव में, पूरे देश की जनता ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक और असम से द्वारका तक, एक मेंडेट देकर उन सारी बातों को ध्वस्त

कर दिया। आज़ादी के बाद पहली बार किसी गैर-कांग्रेसी दल की सरकार बनी और वह थी, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार।

सभापति महोदय, 30 साल के बाद किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिला, किसी एक दल को मेंडेट मिला कि आइए, आपनी पॉलिसी के आधार पर इस देश को आगे ले जाइए और इस देश की जनता के मन में जो सवाल हैं, इस देश की जो समस्याएं हैं, आप उनका समाधान ढूंढ़िए। यह मेंडेट अपने आप में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक मेंडेट था और यह मेंडेट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिला। हम चुनाव में गठबंधन के साथ गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद भी हमने एनडीए को सरकार में सम्मिलित किया और सारे एनडीए के साथियों ने, हमारी भावनाओं को स्वीकार करते हुए, आज इस सरकार की यात्रा को आगे बढ़ाया है।

महोदय, जब किसी सरकार की रचना होती है, तो उसका एक महत्वपूर्ण अंग होता है, नेता का चुनाव। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपने प्रधान मंत्री पद के प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया था, परन्तु यहीं, सेंट्रल हॉल में एनडीए के सारे चुने हुए सांसदों की बैठक हुई, जिसमें नेता के चयन की प्रक्रिया हुई और मुझे इस बात का गौरव है कि मैं भी उस प्रक्रिया का एक हिस्सा था।

सभापति महोदय, जब श्री नरेन्द्र मोदी जी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया था, उस वक्त नरेन्द्र भाई ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि जो सरकार बनने जा रही है, वह गरीबों की सरकार होगी, वह किसानों की सरकार होगी, वह दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की सरकार होगी, वह युवाओं की सरकार

होगी, वह महिलाओं की सरकार होगी और वह गांधी और दीनदयाल जी के स्वप्नों को पूर्ण करने वाली सरकार होगी, गांधी और दीनदयाल जी के रास्ते पर चलने वाली सरकार होगी।

सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए बहुत आनन्द हो रहा है कि आज साढ़े तीन साल हो गए हैं और इन साढ़े तीन सालों में यह सरकार अंत्योदय के सिद्धांत के आधार पर चली है। यह अंत्योदय का सिद्धांत क्या है? आज अगर आपके माध्यम से इस सदन के सदस्यों के सामने मैं इसको सरल भाषा में रखूं, तो कहना चाहूंगा कि अंत्योदय का सिद्धांत वह है, जो विकास की पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है, उसको विकास की पंक्ति में अग्रिम खड़े हुए व्यक्ति के बराबर कर देना या इस प्रकार से आगे बढ़ना कि सबको एक समान विकास मिले।

माननीय सभापति महोदय, आज जब हम साढ़े तीन साल के बाद पीछे मुड़ कर देखते हैं, तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इस देश के संसदीय लोकतंत्र का इतिहास इतना छोटा नहीं है, हमारे संसदीय लोकतंत्र को 70 साल हो गए हैं। इन 70 सालों में कई सरकारें आईं और कई सरकारें गईं। जब सरकारें 25-30 या 35 साल चलती हैं, तब दो-तीन ऐसे बड़े काम होते हैं, जिनको इतिहास में दर्ज करना पड़ता है, लेकिन यह सरकार साढ़े तीन साल चली है, लेकिन पचास से ज्यादा ऐसे काम हैं, जिनको इस देश के इतिहास में स्थान मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने अपने अंत्योदय के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए, अंत्योदय के सिद्धांतों को लागू करने के लिए, शुरू से ही गरीबों के

जीवन स्तर को उठाने के लिए बहुत सूझ-बूझ के साथ, सातत्य के साथ, टुकड़ों-टुकड़ों में नहीं, कंटीन्युइटी के साथ विकास करना तय किया और इस क्रम में जो सबसे पहला काम किया गया, वह है जन-धन बैंक एकाउंट खोलने का काम।

सभापति महोदय, इस देश की 70 साल की आज़ादी में 55 साल तक एक ही पार्टी का राज रहा है और यदि मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करूं, तो कहना चाहूंगा कि एक ही परिवार का शासन रहा है। मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि 70 साल की आज़ादी के अंदर, 55 साल के कांग्रेस शासन के बाद 60 प्रतिशत लोग ऐसे थे, जिनके घर में एक भी बैंक एकाउंट नहीं था। आप व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए, पूरी फैमिली के अंदर, एक बैंक एकाउंट भी नहीं था। वे सरकारें किस तरह से चली होंगी? उन सरकारों का विज़न क्या होगा? उन सरकारों का दृष्टिकोण क्या होगा कि वे 70 साल की आज़ादी के बाद एक गरीब व्यक्ति के घर में एक बैंक एकाउंट भी नहीं दे पाए। जब प्रधान मंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से यह घोषणा की हम जन-धन योजना की शुरुआत करेंगे और हर घर में मिनिमम एक बैंक एकाउंट पहुंचाएंगे, तब मेरा मन भी आशंकित था। मैं सोच रहा था कि जो काम 60 साल में नहीं हुआ, वह कैसे हो जाएगा? मगर आज देखिए साहब, इस देश में गरीबों के 31 करोड़ बैंक एकाउंट खोले गए हैं और हर परिवार में एक बैंक एकाउंट उपलब्ध है। आज शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा, जिसका बैंक एकाउंट न हो।

(1E/RPM पर जारी)

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह (क्रमागत): सभापति महोदय, हमारी मीमांसा की जाती थी और हमारे ऊपर टीका-टिप्पणी की जाती थी कि बैंक एकाउंट तो दे दिया, उसमें जमा कराने के लिए पैसे कहां से आएंगे और गरीब उसमें क्या जमा करेगा ? वैसे तो हमने ज़ीरो बैलेंस की व्यवस्था की थी, मगर मैं कहना चाहता हूं कि जब ये जन-धन योजना के अन्तर्गत लगभग 31 करोड़ एकाउंट खुले, तो उनमें 73 हजार करोड़ रुपए जमा हुए हैं। गरीबों की गाढ़ी कमाई के इतने रुपए उन एकाउंट्स में जमा हैं। जो गरीब पहले उसे अपनी झोंपड़ी में रखता था, अपने गल्ले में रखता था, उसके इस धन की कभी चोरी हो जाती थी या साहूकार के यहां रखता था, तो कभी लुट जाता था, लेकिन आज वह पैसा बैंक एकाउंट्स में सुरक्षित है और वह अपने आपको इस देश के अर्थतंत्र के साथ जुड़ा हुआ पाता है।

सभापति महोदय, वर्ष 2014 में जब यह योजना शुरू हुई थी, उस समय 77 प्रतिशत zero balance accounts थे और आज उनकी संख्या घटते-घटते 20 प्रतिशत से कम हो गई है। सभी गरीब अपने बैंक एकाउंट्स का उपयोग करने लगे हैं। मैं मानता हूं कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

सभापति महोदय, इस देश में जिस प्रकार से वोट की पोलिटिक्स चलती है, उसे देखते हुए किसी को किसी चीज को छोड़ने के लिए कहना लुप्त होता दिखाई पड़ रहा है। यदि इतिहास, पास्ट या भूतकाल में जाकर देखें, तो सबसे अंतिम घटना उस समय की है जब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी इस देश के प्रधान मंत्री थे, तब उन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध के वक्त कहा था कि इस देश के पास चावल नहीं हैं, इसलिए शनिवार को

सभी लोग उपवास करें, यानी एक समय का खाना छोड़ दें। ....(व्यवधान)...त्रिपाठी जी, धन्यवाद। आपने ठीक कहा-सोमवार। उस समय तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। सोमवार को खाना छोड़ दें और उस समय सभी लोगों ने उनकी इस बात का सम्मान किया।

सभापति महोदय, शास्त्री जी के बाद, पहली बार ऐसी हिम्मत, इस देश के अभी के प्रधान मंत्री और हमारे नेता, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने की है। उन्होंने कहा जो सम्पन्न लोग हैं, जिन पर ईश्वर की कृपा है, जिन्हें आर्थिक दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं है, वे लोग अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ दें। इस गैस की सब्सिडी को सरकार गरीबों को देना चाहती है, दलितों को देना चाहती है और ग्रामीण गरीबों को देना चाहती है। मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि 1 करोड़ 23 लाख लोगों ने प्रधान मंत्री की अपील को सम्मान देते हुए गैस की सब्सिडी को छोड़ा है। उसके बाद क्या किया, यदि कोई और प्रधान मंत्री होता, तो वित्तीय घाटा कम कर लेता और उस सब्सिडी को तिजोरी में जमा कर लेता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार तथा हमारे प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस बची हुई सब्सिडी में खजाने का और पैसा लगाकर 'उज्ज्वला योजना' शुरू की।

सभापति महोदय, 70 साल की आजादी के बाद, डेढ़ करोड़ ग्रामीणों के पास गैस नहीं थी। उनकी झोंपड़ी में गैस का चूल्हा नहीं था। स्वच्छ ईंधन नहीं था। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार ने तथा हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक संवेदनशील फैसला लिया कि पांच साल में पांच करोड़ गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर देंगे। अभी इस

सरकार को लगभग साढ़े तीन साल हुए हैं और 3 करोड़ 30 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर देने का काम पूरा कर लिया गया है और इसी बजट में यह सरकार 5 करोड़ की जगह 8 करोड़ लोगों को सिलेंडर देने का प्रयास कर रही है।

सभापति महोदय, आज हमारे सदन में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जिन्हें लगता है कि 21वीं सदी में गैस का सिलेंडर विकास का पैमाना हो सकता है। मैं कोई गरीब के घर में पैदा नहीं हुआ, लेकिन गरीबी को मैंने देखा है। गांवों और जंगलों में जितने आदिवासी हैं, उन्हें देखा है। पूर्वांचल में गरीबों को देखा है। एक बूढ़ी मां जब अपनी झोंपड़ी के अंदर कंडे और टहनियां जलाकर रसोई बनाती है या खाना बनाती है और उसकी पूरी झोंपड़ी जब धुएं से भर जाती है, तो कोई बुरी आदत नहीं होने के बावजूद भी 400 सिगरेट जितना धुआं उस मां के फेफड़ों के अंदर घुस जाता है और उसके स्वास्थ्य को शनैः-शनैः हानि पहुंचाता रहता है।

सभापति महोदय, हमारी सरकार और हमारे प्रधान मंत्री जी ने करोड़ों मांओं को धुआंमुक्त घर देकर, उन्हें, उनके बच्चों, उस घर के बूढ़ों और स्वयं मां के लिए एक स्वच्छ घर निर्माण करने का काम किया है।

(1एफ/पीएसवी पर जारी)

PSV-SK/1F/2.15

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह (क्रमागत): मुझे इस बात का विशेष आनन्द है कि ये जो 3 करोड़ 30 लाख कनेक्शंस दिये, उनमें से 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति की महिलाओं

को मिले हैं और 13 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, ऐसा ही एक फैसला शौचालय का हुआ। इसको स्वच्छता के अभियान के साथ जोड़ा गया। मगर यह स्वच्छता के अलावा भी अपने गरीब के जीवन में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। सभापति महोदय, घर में शौचालय न होना-- आज दिल्ली के लुटियन्स ज़ोन में रहने वाले लोगों को इसका महत्व मालूम नहीं पड़ता है। काफी लोग ऐसे हैं, जिनको इस तकलीफ़ का ज्ञान ही नहीं होगा। परन्तु, सभापति महोदय, एक गरीब के घर की कल्पना करिए, जिसकी एक 16 साल की बच्ची सुबह कुदरती प्रक्रिया के लिए गाँव के बीच से गुजर कर खुले में शौच क्रिया के लिए बैठती है और जब पूरे गाँव की नजर उस पर पड़ती है, तो वह बच्ची अपनी आँखें झुका लेती है। धीरे-धीरे उसका आत्मविश्वास हर रोज़, तिल-तिल कर टूटता है। उस बच्ची को अभी तय करना है कि मुझे कलेक्टर बनना है, डीएसपी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, देश के विकास में मैं किस तरह से अपना योगदान करूँगी, लेकिन उसका आत्मविश्वास 16 साल की उम्र में ही टूट जाता है। वह देश के विकास की प्रक्रिया में आत्मविश्वास के साथ हिस्सेदार नहीं हो सकती। इसके दर्द को कोई सरकार इतने सालों तक नहीं समझी। बहुत सारे लोग योजना लेकर आये, मैं ऐसा नहीं कहता कि यह पहली योजना है, मगर योजना का स्केल देखिए। सभापति महोदय, हम 2022 में हर घर में शौचालय की व्यवस्था कर देंगे और 7 करोड़ के लक्ष्य को समाप्त कर दिया जायेगा। सभापति महोदय, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो आंकड़े देखते हैं,

उनको यह उपलब्धि नहीं दिखाई पड़ेगी। परन्तु एक घर में शौचालय पहुँचने से स्वास्थ्य तो सुधरता ही सुधरता है, महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी मिलता है। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्तुत्य कदम उठाया है। मैं यहाँ इसलिए यह कहना चाहता हूँ ताकि देश भर में संदेश जाये। उन्होंने शौचालय को एक नया नाम देने का काम किया है। उन्होंने शौचालय को 'इज्जत घर' का नाम देने का काम किया है। महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार ने शौचालय योजना के माध्यम से किया है।

सभापति महोदय, गरीब के लिए घर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। कहीं वृक्ष के नीचे प्लास्टिक की शीट पर सो जाना, कहीं वृक्ष के नीचे सो जाना, कहीं फुटपाथ पर या कहीं सर्दियों में बने हुए अस्थायी आवासों में रहना, यह उसका भाग्य बन गया था। हर व्यक्ति को घर देने का स्वप्न भी इस सरकार ने ही देखा है और द्रुत गति से इसकी समाप्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण विस्तारों में एक करोड़ 35 लाख आवास की योजना को मंजूर कर दिया गया है और शहरी क्षेत्रों में 70 लाख आवासों को बनाने का काम शुरू कर दिया गया है।

सभापति महोदय, इस सदन की चारदीवारों ने 'बेरोजगारी' शब्द का प्रयोग बहुत बार सुना होगा, बेरोजगारी पर बहुत बड़े-बड़े अभ्यस्त भाषण भी देखे होंगे, सुने भी होंगे। ...(व्यवधान)... आप पूरा सुन लीजिए। ...(व्यवधान)... आंकड़ों के बहुत से भाषण भी सुने होंगे। बड़े-बड़े विद्वान अर्थशास्त्रियों को भी सुना होगा। मगर इस समस्या का समाधान कोई नहीं कर सका। मैं भी सुन रहा था, जब इस सदन के सदस्य, आनन्द

शर्मा जी और बाकी सदस्य चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा बहुत तरीके से उठाया। यह वाजिब है। देश में बेरोजगारी की समस्या है। मैं इनकार नहीं करता। मैं मानता हूँ कि इस देश में भी बेरोजगारी की समस्या है। मगर 55 साल आपके शासन करने के बाद भी अगर यह समस्या है, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसका समाधान किसने नहीं ढूँढ़ा? हम तो 6 साल, 7 साल, 8 साल से ही काम कर रहे हैं। इस देश को चलाने का सौभाग्य हमें 8 साल के लिए मिला है। इतनी विकराल समस्या कोई 8 साल में उत्पन्न नहीं हुई है। जिस पार्टी ने इस देश पर 55 साल शासन किया, वह आज इस समस्या की बात उठा रही है, मगर मुझे इसका आनन्द है कि हमने इसका समाधान ढूँढ़ा।

सभापति महोदय, स्किल इंडिया, बेरोजगार युवाओं को स्किल्ड बनाना, स्टार्टअप, स्टैंडअप और अन्त में मुद्रा बैंक। मैं इस मुद्रा बैंक के लिए विशेष रूप से इस सभा गृह का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इसलिए, क्योंकि इंदिरा जी का जमाना था। वे हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री थीं। उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने इस देश के बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। उस वक्त क्या उनका भाषण था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के बाद बैंकों के दरवाजे गरीब के लिए खुल गये हैं!

(1जी/वीएनके पर जारी)

VNK-YSR/1G/2.20

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह (क्रमागत) : मगर इतने सालों तक बैंकों के दरवाजे गरीबों के लिए नहीं खुले, न उनके पास अकांउट था, न उनको लोन मिलता था। लोन लेने के

लिए जाते ही उनसे इनकम टैक्स नंबर मांगा जाता था। उसकी समस्या ही यही है कि उसको इनकम ही नहीं है, तो वह इनकम टैक्स नंबर कहां से लाएगा? उसको इनकम नहीं है, यही तो उसका सबसे प्रमुख प्रश्न है। ये बेरोजगार युवा दिशाविहीन होकर भटकते थे। आज मुद्रा बैंक के कारण साढ़े दस करोड़ युवाओं को दस हजार से लेकर दस लाख रुपए तक का लोन देने का काम समाप्त कर दिया गया है और इसके तहत लगभग साढ़े चार लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। सभापति महोदय, इसमें न गारंटी देनी है, न गारंटर लाना है, सूद भी कम रखा गया है। अभी-अभी मैं पढ़ रहा था, चिदम्बरम साहब का ट्वीट पढ़ रहा था कि मुद्रा बैंक के तहत किसी ने पकोड़े बनाने का ठेला लगा दिया, इसको रोजगारी कहते हैं? हां, मैं मानता हूँ कि बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कोई युवा मजदूरी करके, मेहनत करके पकोड़े बनाने का काम करता है। अपने परिश्रम से, पसीना बहा कर, हजारों-लाखों-करोड़ों युवा, जो स्वरोजगारी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, पकोड़े बनाने का काम कर रहे हैं, छोटी-छोटी स्वरोजगारी कर रहे हैं, उनको आप भिक्षुक के साथ compare करेंगे? यह किस प्रकार की मानसिकता है? सभापति महोदय, पकोड़े बनाना कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि इसको भिक्षुक के साथ compare करना शर्म की बात है। सभापति महोदय, वह बेरोजगार था, आज पकोड़े बनाने का काम कर रहा है, उसकी दूसरी पीढ़ी आगे आएगी, इस देश का बड़ा उद्योगपति बनेगी। कोई चाय वाले का बेटा आज प्रधान मंत्री बन कर इस सदन में बैठा है।...(व्यवधान)... इनको मालूम नहीं है कि पकोड़े बनाने वाले का भी उतना ही महत्व है...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please. आपको क्या बीमारी है? आपके नेता हैं, वे बाद में बोलेंगे। वे effectively counter करेंगे, आपको क्यों चिंता है? उनकी सामर्थ्य के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए।

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह : सभापति महोदय, मैं मानता हूँ कि अपने परिश्रम से, अपना पसीना बहा कर अपने जीवन का यापन करने वाला हर व्यक्ति उतना ही बड़ा है, जितने हम इस सदन में बैठे हुए लोग हैं।

सभापति महोदय, जहां तक बिजली का सवाल है, इस देश में 70 साल की आज़ादी के बाद जब हमें इस देश की जनता ने शासन दिया, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथी दलों को शासन दिया, उस वक्त इस देश के अंदर 18 हजार गांव ऐसे थे, जहां बिजली छोड़ दीजिए, बिजली का खंभा या wire भी नहीं पहुंची थी। 18 हजार गांव! सभापति महोदय, मुझे आनंद है कि इस सरकार ने साढ़े तीन साल में 18 हजार में से 16 हजार गांवों में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया है। यह कोई कोरा वादा नहीं है। सरकार के विभाग की साइट पर इसकी सूची पड़ी हुई है, प्रांतवार सूची पड़ी है। 16 हजार गांवों में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया है और अठारहवीं सदी में जीते हुए उन गांवों को इक्कीसवीं सदी में लाने का काम इस देश के प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने किया है।

सभापति महोदय, बिजली गांवों में तो पहुंच गई, इसके बाद घर का क्या? घर में जब तक बिजली नहीं पहुंचती, उसके जीवन-स्तर को ऊपर नहीं उठाया जा सकता। बिजली के साथ शिक्षा जुड़ी है, बिजली के साथ स्वास्थ्य जुड़ा है, बिजली के साथ

स्वच्छता जुड़ी है, इन सारी चीजों को गरीब के घर में कैसे पहुंचाएं? इसके लिए सौभाग्य योजना का विचार आया और सौभाग्य योजना के तहत 2022 तक इस देश के हर गरीब को मुफ्त बिजली का कनेक्शन देने का निर्धारण इस सरकार ने किया है और चार करोड़ कनेक्शन 16 हजार करोड़ रुपए की कॉस्ट से देने की शुरुआत हो गई है।

सभापति महोदय, मैं मानता हूँ कि हर गरीब के घर में शौचालय बनवाना, हर गरीब के घर में गैस पहुंचाना, हर गरीब के घर में रोजगारी पहुंचाना, हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाना, हर गरीब के घर में स्वास्थ्य पहुंचाना, इसी के लिए तो देश को आज़ाद करने के लिए हमारे पुरखों ने यह लड़ाई लड़ी थी। यह लड़ाई इसीलिए लड़ी थी और यह सरकार उसी दिशा में जा रही है।

जब कोई गरीब अकस्मात अस्वस्थ हो जाता है या बीमार हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना? यह सरकार इसके लिए दो योजनाएं लाई। बहुत कम यानी मामूली से प्रीमियम में प्रधान मंत्री सुरक्षा योजना के तहत 13 करोड़ से ज्यादा गरीबों को सुरक्षा देने का काम समाप्त कर दिया गया है और प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत साढ़े पांच करोड़, कुल मिला कर 18 करोड़ से ज्यादा गरीबों को सुरक्षित करने का काम किया गया है। जन-औषधि केन्द्र के माध्यम से, 3 हजार से ज्यादा पीएमबीजेपी केन्द्र से 800 से ज्यादा दवाइयां दस प्रतिशत से तीस प्रतिशत दाम पर गरीब के लिए उपलब्ध करा दी है। भगवान न करे कि किसी गरीब को दिल की बीमारी हो जाए, स्टेंट लगाने की जरूरत पड़ जाए, तो स्टेंट की कीमत सुन कर ही उसको पहले अटैक आ जाता था।

(1एच/एनकेआर-बीएचएस पर जारी)

NKR-BHS/1H/2.25

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह (क्रमागत) : पहले जो 4 लाख रुपए का स्टेंट मिलता था, उसे 40,000 रुपए में और फिर 40,000 रुपए के स्टेंट को 8,000 रुपए में देने हेतु इस सरकार ने बजट उपलब्ध कराया है। Artificial घुटने बिठाने के लिए पहले जो खर्च आता था, उसे भी बहुत कम कर दिया गया है।

सभापति महोदय, मैं बड़े ध्यान से देख रहा था, जब वित्त मंत्री जी सदन में बजट प्रस्तुत कर रहे थे। इस बजट में प्रधान मंत्री जी 'आयुष्मान भव योजना' लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत इस देश के 40 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य का खर्च बीमा के माध्यम से मिलने जा रहा है। मैं मानता हूं कि पूरी दुनिया में जितने भी लोकतंत्र हैं, उन सब की लोक-कल्याण की योजनाओं को आप खंगालकर देख लें, देश के 50 करोड़ लोगों को बीमा सुरक्षा देना, हैल्थ बीमा देना और 5 लाख रुपए का बीमा देने का काम सिर्फ हमारी भारतीय जनता पार्टी, एन.डी.ए. की सरकार और माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मुझे मालूम है कि अब सामने से थोड़ी आवाज़ उठेगी, क्योंकि 'आयुष्मान भव भारत' को अब 'नमो हैल्थ' के नाम से इस देश में लागू किया जाएगा जिससे देश की जनता लाभान्वित होगी।

सभापति महोदय, कम्युनिस्टों के समर्थन से चलने वाली यूपीए- । सरकार ने भी न्यूनतम वेतन में इतना इज़ाफा नहीं किया था, जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमारी सरकार द्वारा इसमें 40 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की

गई है। इसी प्रकार गरीब कल्याण के लिए इस सरकार ने अन्त्योदय के सिद्धांतों को, दीनदयाल जी के सिद्धांतों को चरितार्थ करने का निर्णय लिया है। मेरे पास बहुत लंबी सूची है, मगर मैं यहां बहुत थोड़े बिन्दु ही उठाना चाहता हूं, क्योंकि अभी अनेक माननीय सदस्य भी बोलेंगे। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि गरीबी हटाओ के नारे से सत्ता में तो बहुत लोग आए, लेकिन वास्तव में गरीबी हटाने या गरीबों का जीवनस्तर उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, 70 प्रतिशत लोगों का जीवन-यापन कृषि पर आधारित उद्योंगों और व्यवसायों पर निर्भर है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साढ़े तीन साल तक सत्यतापूर्वक तरीके से कृषि के सभी अंग-उपांगों को समाविष्ट करते हुए, कृषि में किसान की आय दोगुनी करने की दिशा में बहुत मजबूत कदम उठाए हैं।

महोदय, प्रधान मंत्री Irrigation योजना अपने आपमें विशिष्ट प्रकार की योजना है, जिसके तहत लगभग डेढ़ लाख हेक्टेयर भूमि माइक्रो-इरिगेशन के अंतर्गत लाई गई है। इससे पानी की बचत तो होगी ही, कृषि उपज में भी बढ़ोतरी होगी। महोदय, 285 नई परियोजनाएं ऐसी हैं, जिनके अंतर्गत 1 करोड़ 88 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई से युक्त कर दिया जाएगा। यह एक बहुत बड़ी परियोजना 'प्रधान मंत्री Irrigation योजना' के तहत शुरू हुई है, जिससे किसानों की किस्मत बदलने वाली है। इसके अलावा 30 नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम को अटलजी की सरकार जाने के बाद छोड़ दिया गया

था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार और एन.डी.ए. की सरकार आने के बाद, उन नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम फिर से आरम्भ किया गया है। सभापति महोदय, अब तक ऐसी तीन योजनाएं शुरू हो चुकी हैं और 30 योजनाएं आने वाले दो साल के अंदर हम हाथ में लेने वाले हैं। इससे देश के irrigated land में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है।

सभापति महोदय, जब कुदरती आपदा आती है, तब किसान के साथ कोई नहीं होता। ऊपर भगवान होता है और नीचे धरती माता होती है। सालों तक इसमें दी जाने वाली राहत के norms को बदला नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी और एन.डी.ए. की सरकार बनने के बाद, पहले ही साल राहत के लिए जो norms बने थे, किसानों की मदद के लिए, उसके amount को डेढ़ गुना किया गया और क्षेत्रफल में चार गुना की बढ़ोतरी की गई है। इस तरह किसान को दोनों तरफ से राहत देने हेतु बहुत बड़ा प्रयास हुआ है। हम वैज्ञानिक assessment की भी एक नई पद्धति लाए हैं, ताकि जिसका नुकसान हुआ है, उसे तुरन्त राहत मिल पाए।

सभापति महोदय, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का जहां तक सवाल है, देश में बहुत सी फसल बीमा योजनाएं आईं, हो सकता है कि अभी जो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना आई है, इससे भी अच्छी योजना लाने का सौभाग्य हमारी ही सरकार को संभव है, 2019 के चुनाव के बाद, फिर से मिले।

(1J/DS द्वारा क्रमागत)

DS-RL/2.30/1J

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह (क्रमागत) : मगर, मैं इतना निश्चित कह सकता हूँ कि यह "प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना" अपने आप में एक सम्पूर्ण प्रधान मंत्री फसल योजना है। अगर बुआई से लेकर खलिहान तक, पूरी प्रक्रिया में कहीं पर भी आपदा आ जाती है, किसी भी प्रकार की आपदा आ जाती है, तो किसान को अपना फसल बीमा मिल पाए, इस प्रकार की व्यवस्था हमने इसके अंदर की है। इसमें हर गाँव का अलग सर्वे किया जाना है। पहले केवल ब्लॉक्स के सर्वे होते थे, लेकिन अब ब्लॉक्स के सर्वे की जगह हर गाँव का सर्वे करने का निर्णय लिया गया है। सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए आनन्द है कि पहले एकाध करोड़ के आस-पास किसान इसका फायदा उठाते थे, लेकिन वर्ष 2016-17 में 5 करोड़ 70 लाख किसानों ने इसका फायदा उठाया है और इसके अंतर्गत 13,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया गया है।

सभापति महोदय, किसान जो उत्पादन करता है, उसके अगर अच्छे दाम नहीं मिलते हैं, तो किसान के हिस्से में कुछ नहीं आता है। धीरे-धीरे इस देश की सभी मण्डियों को ई-मण्डी में तब्दील करने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है। अभी काम थोड़ा धीरे चल रहा है, मगर दिशा सही है। 455 मण्डियों को ई-मण्डी में कन्वर्ट कर दिया गया है और 31,000 करोड़ रुपये की बिक्री और क्रय इन्हीं मण्डियों के माध्यम से गत वित्तीय साल के अंदर हुआ है। मैं मानता हूँ कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

सभापति महोदय, जब से मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ, यूरिया की किल्लत को हमने देखा है। गुजरात में तो यूरिया के कारखाने अभी भी चल रहे हैं, फिर भी गुजरात में किल्लत होती थी। जो उत्तर के राज्य हैं, वहाँ पर तो यूरिया के लिए लाठी भाँजने का

समय आता था। चाहे रबी हो या खरीफ, किसान को आन्दोलन किए बगैर यूरिया नहीं मिलता था। यूरिया का उत्पादन तो कम था ही, परंतु यूरिया की कालाबाजारी भी बहुत बड़ी मात्रा में चल रही थी। सभापति महोदय, एक ही निर्णय, नीम-कोटेड यूरिया का किया गया। नीम-कोटेड यूरिया के कारण यूरिया का इंडस्ट्रीज़ में उपयोग समाप्त हो गया, वे कर ही नहीं सकते। इस नीम-कोटेड यूरिया के कारण इंडस्ट्री में जाने वाला यूरिया बाजार में आ गया, जिसके कारण आज सब किसानों को यूरिया मिलता है। यूरिया की खपत भी अब कम हो गई है और पेस्टिसाइड्स का खर्च भी कम हो गया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सारे सभासदों से यह कहना चाहता हूँ कि गोरखपुर, सिन्दरी, बरौनी, तालचर और रामगुंडम के कारखानों में से हमने एक भी नया नहीं बनाया है। ये अलग-अलग सरकारों के समय में बन्द पड़ गए थे, जिनको चालू करने की सुध नहीं ली गई थी, ये छः के छः कारखाने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से चालू किए। इन छः कारखानों के शुरू होने के बाद मुझे भरोसा है कि यूरिया इस देश में इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि नीम-कोटेड यूरिया के कारण उसकी खपत कम हुई है और इन छः कारखानों में उत्पादन शुरू होने के बाद ऐसा हुआ है।

सभापति महोदय, डेयरी के लिए भी 11,000 करोड़ रुपये की योजना रखी गई है। जैविक खेती के लिए भी एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। लगभग साढ़े 22 लाख हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती के नीचे लाने का काम कर दिया गया है।

सभापति महोदय, Soil Health Card पर मैं इसलिए विस्तार में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यह एक नई चीज़ है और इस सदन के माध्यम से देश के किसानों तक इसकी बात जानी चाहिए। देश का किसान, जो अपने खेत-खलिहान के अंदर रहता है और हरदम पसीना बहाता है, उसको मालूम नहीं है कि उसकी मिट्टी में क्या चीज़ पड़ी है, प्लस क्या है, माइनस क्या है, उसके अंदर कौन-सी क्रॉप होगी, यह उसको मालूम नहीं है, उसमें कितना पानी चाहिए, वह मालूम नहीं है, उसकी मिट्टी के तत्व क्या हैं, वह भी उसको मालूम नहीं हैं। उसमें कौन-सी खाद कितनी चाहिए, वह भी उसको मालूम नहीं है। पहले ये सारी चीज़ें लैबोरेटरीज़ के अंदर पड़ी होती थीं। सभापति महोदय, गुजरात में Soil Health Card का एक प्रयोग किया गया और हर किसान को उसकी अपनी भूमि का हेल्थ कार्ड दिया गया। उस हेल्थ कार्ड के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि उसकी मिट्टी किस प्रकार की है, उसमें कौन-सी क्रॉप्स अच्छी हो सकती हैं, उसमें कितना पानी चाहिए, कौन-सी खाद चाहिए। उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं और 14 भाषाओं में लिखी हुई होती हैं, स्थानीय भाषाओं में लिखी हुई होती हैं। लगभग साढ़े तीन करोड़ से ज्यादा किसानों को Soil Health Card देने का काम इन तीन साल के अंदर समाप्त कर दिया गया है, 460 full-fledged प्रयोगशालाएँ बना दी गई हैं और 4,000 मिनी लैब्स बनाने का काम भी एक तरीके से शुरू हो गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं किसानों के बारे में सबसे अंतिम बात यही कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के 70 साल के अंदर किसान को उसकी लागत से डेढ़ गुना

समर्थन मूल्य देना एक पोलिटिकल नारा तो होता था और सबको लगता था कि यह एक पोलिटिकल नारा है। जब एक पार्टी सत्ता में होती थी, तो उसके खिलाफ इसको दूसरी पार्टी उपयोग करती थी और जब दूसरी पार्टी सत्ता में आती थी, तो पहली पार्टी इसका उपयोग करती थी, लेकिन अब हमने यह व्यवस्था की है कि इसका उपयोग कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने हर फसल के लिए, चाहे वह रबी हो या खरीफ, उसकी लागत से डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का निर्णय लिया है।

(1के/एमसीएम पर जारी)

MCM-DC/1K/2.35

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह (क्रमागत) : मैं मानता हूं आज़ाद हिन्दुस्तान में यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। सभापति महोदय, इस के कारण ही किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसमें White क्रांति, Blue क्रांति, नई Green क्रांति, micro-irrigation इन सारी चीजों को समाहित करते हुए यह कदम भी किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में जाएगा। सभापति महोदय, यह सरकार जब से चली, इस सरकार का एक सिद्धांत रहा है कि हम फैसले ऐसे नहीं लेते हैं जो लोगों को अच्छे लगते हैं। सभापति महोदय, vote bank जेनरेट करने के लिए लोगों को अच्छे लगें, ऐसे फैसले लेने वाली सरकार हमने देखी है। यह सरकार ऐसी है जो लोगों के लिए अच्छे हों, ऐसे फैसले लेती है, लोगों को अच्छे लगें, ऐसे फैसले नहीं लेती है। सभापति महोदय, financial discipline के कारण सारे parameters improve हुए हैं , मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता, हमारे साथी बोलेंगे। Agricultural growth rate जो मायनस .2

परसेंट था , वह 4.1 पर जाकर ठहरा है, मुद्रास्फीति 9.5 से 1.5 तक पहुंची है,.....(व्यवधान)....

MR. CHAIRMAN: Please. ...(Interruptions)...

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह : Interest rate 8 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक चला है, चालू खाता घाटा, राजकोषीय घाटा यह सब अपने पैरामीटर्स को छूते हैं। FDI inflow भी बढ़ा है, अब तक का रिकॉर्ड Forex reserve 460 बिलियन डॉलर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासन में है, नरेन्द्र मोदी जी के शासन में है और इसके कारण बहुत सारे reforms भी किए गए हैं और इन reforms के कारण बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों में से सरकार ने अपनी अंक तालिका में अंकों की छलांग लगाई है, चाहे वह Ease of Doing Business की ranking हो, getting electricity की रैंकिंग हो, Globalization Index हो, Global Competitiveness Index हो। बहुत सारी चीजों में हमने रैंक को आगे बढ़ाया है।

सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सबसे अच्छा काम अगर किया गया है तो इस देश के मौसमों के हिसाब से बजट को लाने का फैसला किया है। पहले हम बजट को लाते थे 28 फरवरी को। पास होते-होते अप्रैल आ जाता था और बाद में मानसून आ जाता था। इस भारतीय जनता पार्टी, एन0डी0ए0 की सरकार ने, इस देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक फैसला लिया कि एक फरवरी को इस देश का बजट आ जाएगा, इसके कारण बजट के implementation में अच्छी सहूलियत हुई है, रेलवे बजट को भी हमने perform कर दिया है।

सभापति महोदय, एक बहुत बड़ा सुधार इस सरकार ने किया है, जिसका नाम है जी0एस0टी0। जी0एस0टी0 अपने आप में एक बहुत बड़ा सुधार है। दुनिया में सबसे बड़ा बिक्री और सेवा कर का अगर कोई सुधार हुआ है तो हिन्दुस्तान का जी0एस0टी0 के प्रति अर्थतंत्र का जो हमारा आकार है, उसमें कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। इतने सारे राज्य, इतने सारे दल, इसमें कभी जी0एस0टी0 इम्प्लीमेंट हो पाएगा, इसकी किसी को कल्पना नहीं थी। आज नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में "एक देश, एक कर" का स्वप्न साकार कर लिया है, पूरे देश में एक समान कर की व्यवस्था हुई है। माननीय सभापति महोदय, इस पर बहुत सारी राजनीति सदन के बाहर हुई। मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में जो सत्य है, हकीकत है वह कहनी चाहिए। सबसे पहले तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जब कांग्रेस की सरकार थी तब जी0एस0टी0 का विरोध किया था। सभापति महोदय, यह बात सत्य नहीं है। मैं बताता हूं सुन लीजिए न, मैं बताता हूं, सुनिए आनन्द जी, आप सुनिए। सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने कभी जी0एस0टी0 का विरोध नहीं किया था, भारतीय जनता पार्टी ने जी0एस0टी0 के तरीकों का विरोध किया था। सरकारों को क्यों भरोसा नहीं था, क्योंकि यू0पी0ए0 सरकार कर सुधार लेकर आई थी। सी0एस0टी0 को 4 परसेंट से घटाकर 2 परसेंट कर लिया था। आपको याद होगा कि 4 परसेंट से घटाकर 2 परसेंट हुआ था। जो राज्यों को घाटा था, वह आप लोगों को चुकाना था।

(1L/SC पर जारी)

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह (क्रमागत) : यूपीए सरकार को चुकाना था, लेकिन वादाखिलाफी हुई, राज्यों को घाटा नहीं चुकाया गया - 37 हज़ार करोड़ रुपये एनडीए सरकार ने चुकाने का काम किया। राज्यों को भरोसा क्यों नहीं था? Federal Structure की भावना को किसने नष्ट किया? जब एक वचन दिया जाता है और उस वचन का पालन नहीं होता है तो कोई भरोसा नहीं करेगा। सब राज्य चिंतित थे। सब राज्य जीएसटी से नहीं डरते थे, जीएसटी के कारण राज्यों पर जो बोझ पड़ने वाला था, उससे डरते थे। सब कहते थे कि implementation के वक्त अगर आय कम हुई तो हम अपने राज्य को कैसे चलाएंगे, राज्य की जनकल्याण की योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाएंगे? राज्य की जनकल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाने के संबंध में उनके मन में एक सवाल था,जिसका समाधान हमारे प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री ने ढूंढ़ा। 14 प्रतिशत रेवेन्यु पर बढ़ोतरी देने का वादा किया गया तब जाकर सभी राज्य सहमत हुए। ..(व्यवधान)..

श्री सभापति : मधुसूदन जी, प्लीज़।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : सर, यह हकीकत नहीं है।..(व्यवधान)..

श्री सभापति : आप बाद में अपनी बात कहिएगा। बाद में जब आपको मौका मिलेगा, तब बोलिएगा।..(व्यवधान).. That will not go on record. Why do you waste your energy?

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह : सभापति महोदय, हमने 14 परसेंट revenue growth का जो वादा किया, वह सिर्फ शाब्दिक वादा नहीं था, वह सीएसटी की तरह शाब्दिक वादा नहीं है, हर राज्य को Constitutional guarantee दी गयी है कि अगर आपकी आय

कम होती है तो भारत सरकार उसका भुगतान करेगी और 22 राज्यों को आज उस नुकसान का भुगतान भारत सरकार कर रही है - इसलिए भरोसा बना है। विरोध इसलिए था कि भरोसा नहीं था, हमने भरोसा पैदा हो, ऐसा काम किया, ऐसा रास्ता ढूंढ़ा, तब जाकर जीएसटी पास हुआ है।

सभापति महोदय, जीएसटी को इतने विकराल तरीके से लोगों के सामने रखा जा रहा है, जैसे बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं, देश का व्यापार बंद हो जाएगा, छोटे और मंझले व्यापारियों की दुकानें बंद हो जाएंगी, लघु उद्योग बंद हो जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने इसकी deep study की है। सभापति महोदय, ऐसा कुछ नही होगा। जीएसटी के कारण देश का व्यापार बढ़ने वाला है, लघु उद्योग और छोटे व्यापारी और मज़बूत होने वाले हैं।

सभापति महोदय, पहले इस देश की स्थिति क्या थी? 17 प्रकार के अलग-अलग टैक्स थे - excise से लेकर octroi तक 17 टैक्स और 23 प्रकार के सेस लगते थे - 17 टैक्स और 23 सेस - उन्हें समाप्त करके एक टैक्स बनाया गया। सभापति महोदय, इससे व्यापारी की दिक्कत कभी बढ़ नहीं सकती है, कम होती है। पहले 15 इंस्पेक्टर्स को अपने books of accounts दिखाने पड़ते थे, आज उन्हें एक ही इंस्पेक्टर से डील करना है। जिन सदस्यों को संशय है कि जीएसटी के माध्यम से दिक्कतें बढ़ेंगी, मेरा आपके माध्यम से उनसे अनुरोध है कि एक बार जब चुंगी की रेड हो जाती है, उस समय आप व्यापारी को जाकर मिलिए। अग्रवाल जी यहां बैठे हैं, उन्हें मालूम है कि जब चुंगी की रेड होती है तब क्या होता है। टोल टैक्स के नाके पर जो एक-एक दिन की लम्बी

ट्रक्स की लाइनें लग जाती थीं, उस वक्त स्थिति क्या होती थी? उस वक्त ट्रक्स का उपयोग कितना कम हो जाता था, उस समय transportation कितना महंगा पड़ता था, यह जरा उनसे पूछिए। 15 इंस्पेक्टर्स की जगह अगर एक इंस्पेक्टर आपके books of accounts को देखेगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यापारी इसका विरोध करेगा। मगर हां, सभापति महोदय, teething problem है, शुरुआती दिक्कतें आयी हैं और शायद अभी भी थोड़ी बाकी होंगी। जब 23 cess और 17 taxes को आप मर्ज कर लेते हैं, एक टैक्स बनाते हैं तो शुरुआती दिक्कतें आती हैं, लेकिन यह सरकार संवेदनशील सरकार है। जीएसटी के आने के तीन महीने के बाद इस सरकार ने एक बहुत बड़ा संवाद का अभियान चलाया। सारे संसद सदस्य, सारे अधिकारी, सारे मंत्री Chamber of Commerce में गए, छोटे व्यापारियों के पास गए, लघु उद्योग वालों के पास गए और उन्हें सुनने की प्रक्रिया की। सभापति महोदय, उस संवाद में से बहुत सारी चीज़ें निकलकर आयीं कि दिक्कतें क्या हैं? उन दिक्कतों को एक-एक करके resolve करने की शुरुआत की और 23 मीटिंग्स में 30 से ज्यादा procedural changes करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये जो सारी मीटिंग्स हुईं, उनमें रेड के लिए हो-हल्ला किया गया।

(1एम-पीआरबी पर जारी)

PRB-KS/1M/2.45

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह (क्रमागत):सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को और देश को बताना चाहता हूं कि 400 चीजों के दाम इन 23 मीटिंगों में कम कर

दिए गए। 1100 में से 150 चीजों को टैक्स फ्री कर दिया गया। लगभग 1100 में से 550 चीजों पर टैक्स कम करने का काम GST आने के बाद इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 30 procedural changes किए हैं और सभापति महोदय, सामान्यतः आम सभाओं में कहा जाता है कि यह जो GST है, केवल भारतीय जनता पार्टी का बेबी है। GST Council बनी है ...(व्यवधान)... GST Council में हर राज्य का मुख्यमंत्री आता है, हर राज्य का वित्त मंत्री आता है और वे GST Council में अपनी-अपनी राय रखते हैं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि GST Council की 23 से 25 मीटिंगें हुई हैं, एक भी प्रस्ताव पर मतदान नहीं हुआ है, सारे के सारे प्रस्ताव unanimous हैं। अगर आप विरोध करते हो, विपक्ष के मित्र अगर विरोध करते हैं तो आपका भी एक मत यहां है और मैं विशेषकर कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहूंगा कि इन 23 मीटिंगों में अलग-अलग 91 मंत्री कांग्रेस शासित राज्यों के आए हैं और उन्होंने सहमति दी है और यह आपकी सहमति से हुआ है। GST Council में एक भाषा, सदन में दूसरी भाषा और आम सभा में तीसरी भाषा यह किस प्रकार की राजनीति है? किस प्रकार से हम देश को आगे बढ़ाएंगे? क्या हम GST council के minutes प्रकाशित करें? आप मुझे सुनो। आपको मुझे 6 साल तक सुनना पड़ेगा। आप मुझे रोक नहीं सकते, सभापति ही रोक सकते हैं। सभापति महोदय, क्या हम इसके minutes को सार्वजनिक करें कि इसमें फलां पार्टी की भी सहमति है, फलां पार्टी की भी सहमति है, फलां पार्टी की सहमति है कोई पार्टी बाकी नहीं है। सबकी सहमति है क्योंकि सर्वानुमति से फैसला हुआ है। सभापति

महोदय, शब्द क्या उपयोग होते हैं - गब्बर सिंह टैक्स। कौन है यह गब्बर सिंह? एक मशहूर हिंदी फिल्म थी शोले। उसमें एक डकैत के पात्र का नाम गब्बर सिंह है। यह डकैत कौन है? कानून से बना हुआ टैक्स वसूल करना क्या डकैती है ? कितनी समझ रखते हैं ये लोग ? जो इसको गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं और गब्बर सिंह टैक्स जाता कहां है, यह GST जाता कहां है ? सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह टैक्स One Rank, One Pension देने के लिए जवानों के bank accounts में जाता है, शहीद की विधवा के bank account में जाता है, गरीब महिला को उज्ज्वला योजना देने के लिए जाता है, गरीब को घर देने के लिए जाता है, सौभाग्य योजना के तहत उसको बिजली देने के लिए जाता है। लोगों को कर न देने के लिए उकसाना, यह राजनीति की अच्छी निशानी नहीं है। हम देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं ? हम सबको सोचना पड़ेगा। यह कोई दल की बात नहीं है। आज हम हैं, कल आप भी आ सकते हो। ...(व्यवधान)... हां, हां, आ सकते हो। ...(व्यवधान)...हमारी मानसिकता ऐसी नहीं है। ...(व्यवधान)... सभापति महोदय, हमारी मानसिकता ऐसी नहीं है कि हमेशा हमारा ही शासन रहेगा। यह लोकतंत्र है, जनता किसी को भी सत्ता में बैठा सकती है, 55 साल आप भी बैठे हो। ...(व्यवधान)... देश इस तरह से नहीं चलता है, देश कुछ मुद्दों में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर चलाना पड़ता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सारे सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि GST इस देश का भविष्य सुधारने वाला एक अच्छा reform है, इसमें आप सब सहयोग करिये। जनता का मन बनाने के लिए सरकार का सहयोग करना चाहिए, ऐसी मैं अपील मात्र कर

सकता हूं। सभापति जी, बाकी तो राजनीति करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र पड़े हैं। सभापति जी, infrastructure के मामले में भी इस सरकार ने बहुत सारे achievements प्राप्त किए हैं। Road construction में लगभग डेढ़ गुना, National Highway construction में दोगुना, National Highway construction के order देने में साढ़े चार गुना, rural road construction में दोगुना, fund के मामले में तीन गुना। 2014 में village connectivity के मामले में 56 प्रतिशत गावों को road से जोड़ा गया था। आज 82 प्रतिशत गावों को roads से जोड़ने का काम समाप्त कर दिया गया है। सभापति महोदय, 5,29,245 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाने का काम समाप्त हो गया है। वर्ष 2013-14 में नई रेलवे लाइन का construction 360 किलोमीटर था और वर्ष 2016-17 में 953 किलोमीटर है। Broad-gauge conversion में 750 किलोमीटर थी इसको 1000 किलोमीटर तक पहुंचाया गया है, double trekking railway line को 500 किलोमीटर से बढ़ाकर 882 किलोमीटर कर दिया गया है और railway outlay को बढ़ाकर ढाई गुना कर दिया गया है। वर्ष 2016-17 में एक लाख 31 हजार करोड़ रुपये रेल विभाग के लिए आवंटित किए गए ।

(1N/GS पर जारी)

GS-RSS/1N/2.50

श्री अमित अनिल चन्द्र (क्रमागत) : ग्रॉस रेवेन्यु में भी 19 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का काम किया है और एयरपोर्ट्स की संख्या को हमने दोबारा चुनाव में जाने से पहले-पहले पांच गुना करने का लक्ष्य रखा है।

सभापति महोदय, मैं बैंकिंग की बात कह चुका हूं, इसलिए आगे इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं।

सभापति महोदय, पावर सेक्टर के अंदर भी बहुत सारा काम हुआ है। Installed Capacity जैसे पहले हमारी 243 मेगावॉट थी, अब यह 333 मेगावॉट है। ट्रांसमिशन कैपेसिटी, जो 2,51,000 किलोमीटर थी, उसको 3, 81,090 किलोमीटर बढ़ाया गया है। पीक पावर डेफिसिट 9 परसेंट था, उसको 1.6 परसेंट तक सीमित कर दिया गया है, मतलब यह है कि पावर सेक्टर की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। Installed Wind Capacity 21 गीगावॉट की जगह 31 गीगावॉट हो गयी है। सोलर पावर टैरिफ 12 रुपये यूनिट खरीदी जाती थी, अब ढाई रुपये यूनिट सोलर पावर खरीदी जाती है। Installed Solar Capacity 2.6 गीगावॉट थी, अब इसकी जगह 12 गीगावॉट कर दी गयी है। Un-electrified Villages की संख्या 18,542 थी और अब सिर्फ 1,948 गांव बिना बिजली के रह गए हैं। कोल प्रोडक्शन 462 मिलियन मीट्रिक टन था, अब यह बढ़कर 556 मिलियन मीट्रिक टन हुआ है। सभापति महोदय, बहुत सारी और भी चीजें हैं, मगर मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है। ...(व्यवधान)... बाकी के लोग बोलेंगे, आप चिंता मत करिए।

सभापति महोदय, किसी भी देश की सुरक्षा प्रत्येक देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। देश की सुरक्षा तब तक ठीक से नहीं हो सकती, जब तक उसका जवान, फौजी अपने आपको सुरक्षित और गौरवान्वित न समझे। इस देश के जवान 40 साल से "वन रैंक, वन पैंशन" की मांग करते थे। अनेक सरकारें आयीं और अनेक सरकारें गयीं, "वन रैंक, वन पैंशन" को कोई छूता नहीं था, अगर किसी ने किया, तो चुनाव के वक्त

पर 100 करोड़ का एक टोकन बजटरी प्रोविजन करके जवानों को झांसा देने का काम किया।

सभापति महोदय, एनडीए की सरकार आयी, भाजपा सरकार आयी, जब नरेन्द्र मोदी प्रधान मंत्री जी बने, हमारा चुनावी वायदा था और हमने एक ही साल में "वन रैंक, वन पैंशन" को लागू करके देश के जवानों को हर साल 8,000 करोड़ रुपया देने का काम किया है, इससे उनका हौसला बढ़ा है।

सभापति महोदय, जवान चाहे 44 डिग्री टेम्परेचर में कच्छ या रेगिस्तान में काम करता हो या माइनस 44 डिग्री टेम्परेचर में पहाड़ों की चोटियों पर काम करता हो, उसके परिवार की चिंता करना, यह सरकार अपना फर्ज़ समझती है और "वन रैंक, वन पैंशन" मैं मानता हूं कि उनके लिए बहुत बड़ी राहत है और इसे लागू करके हमने उनकी समस्या का समाधान कर दिया है।

सभापति महोदय, इस देश में कई बार आतंकवादी हमले हुए। आतंकवादी हमले देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले जवानों के थानों पर भी हुए हैं, इनके कैम्पों पर भी हमले हुए और बहुत सारे जवान हताहत भी हुए हैं। मगर इतने सारे समय के अंदर किसी ने भी इसका जवाब देना उचित नहीं समझा था। एक दिन सबेरे उरी में तड़के, सुबह तीन बजे पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमला किया, 12 जवानों को जिंदा जला दिया गया। यह कायरतापूर्ण हमला था और उनको लड़ने का मौका भी नहीं दिया गया। वहां पर जिंदा जवान जल गए, सोते-सोते जवान जल गए। पूरे देश में गुस्सा था, आक्रोश था और हताशा थी कि अब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। पहले क्या

हुआ था, प्रधान मंत्री जी का एक स्टेटमेंट आएगा, सब दुख व्यक्त करेंगे, आक्रोश व्यक्त करेंगे और फिर बात समाप्त हो जाएगी। सभापति महोदय, इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी थे, वे एक शब्द भी नहीं बोले, उनकी तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। दस दिन के अंदर, अपनी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला किया और अपने वीर जवान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की सीमा के अंदर जाकर, आतंकवादियों से अपने जवानों का बदला लेकर सुरक्षित वापस आ गए।

(HMS/1O पर जारी)

HMS-/1O/2.55

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह (क्रमागत) : और जिस क्षण ये जवान वापस आए, वह क्षण देश की सुरक्षा के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था और उसी क्षण दुनिया का देश को देखने का नज़रिया बदल गया। दुनिया को लगा कि अमेरिका और इजरायल के बाद भारत एक ऐसा देश है, जो अपनी सीमाओं और जवानों की सुरक्षा ठीक प्रकार कर सकता है। सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि इस से दुनिया का भारत को देखने का नज़रिया बदला है। देश की सुरक्षा कितनी अहम है, इस का परिचय देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने surgical strike के माध्यम से दिया है। महोदय, बाद में भी तीनों सेनाओं के modernisation के संबंध में, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है क्योंकि मैं पक्ष-विपक्ष की बात नहीं करता, मगर हमारे शासन में आने के समय यह काम ठप्प था। हमने 10 साल का blueprint बनाकर तीनों सेनाओं के modernisation के काम को

आगे बढ़ाया है और तीनों सेनाओं को अत्याधुनिक हथियारों से लैस बनाने का काम किया है। हमने इनकी संचार व्यवस्था को भी चुस्त-दुरुस्त करने का काम किया है। महोदय, आंतरिक सुरक्षा के लिए भी 18,000 करोड़ रुपए police modernisation के लिए दिए गए हैं।

सभापति महोदय, police modernisation बी0जे0पी0 के साथ जुड़ा शब्द है। यह इसलिए बी0जे0पी0 के साथ जुड़ा है क्योंकि पहले जब एन0डी0ए0 की सरकार आयी थी, तो modernisation शुरू हुआ था। बाद में एन0डी0ए0 की सरकार गयी और यू0पी0ए0 की सरकार आयी, तो modernisation बंद हो गया था। अब फिर से एन0डी0ए0 की सरकार आने के बाद police modernisation शुरू हुआ है। महोदय, सुरक्षा बलों को आंतरिक सुरक्षा के लिए मजबूत बनाना, उनका modernisation करना इस सरकार की priority है और इस कार्य को हमने आगे बढ़ाया है।

सभापति महोदय, कश्मीर समस्या हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। हमने जब वहां नई सरकार बनने के बाद शासन संभाला और कड़ाई शुरू हुई तो देशभर में सब लोगों में एक चर्चा चली कि इस सरकार की कश्मीर नीति सफल है या विफल है? यह कैसी नीति है? हम किस दिशा में जा रहे हैं? कश्मीर हमारे हाथ से तो नहीं चला जाएगा? मगर आज मैं कह सकता हूं कि कश्मीर विगत 35 सालों में सब से ज्यादा सुरक्षित और शांत प्रदेश है। आज हवाला के माध्यम से पैसा लेकर अलगाववाद और terrorism फैलाने वाले सारे लोग तिहाड़ जेल के अंदर अपने दिन काट रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस तरह हमने कश्मीर की समस्या को बहुत अच्छे तरीके से handle किया है।

महोदय, सरकार ने सामाजिक बदलाव के लिए भी बहुत सारे कार्य किए हैं। सब से पहला काम काका साहेब कालेलकर कमीशन के वक्त से इस देश का पिछड़ा वर्ग इस घड़ी की प्रतीक्षा में था कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता मिले। भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने इस संबंध में फैसला लिया और पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का बिल दूसरे सदन से पास किया है। इस तरह देश के करोड़ों पिछड़ा वर्ग के लोगों की आशा व अपेक्षा को पूरा करने के लिए हम बिल लेकर आए। हमने यह बिल लोक सभा से पारित करा दिया, मगर अभी तक, महोदय "अभी तक" शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, अभी तक यहां वह बिल पास नहीं हो सका है क्योंकि यहां हमारा बहुमत नहीं है।

श्री नरेश अग्रवाल : आप बिल लाइए, हम पास कराने के लिए तैयार हैं।

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह : हम तो लेकर आए थे और यह बात रिकॉर्ड पर है कि स0पा0 समर्थन करेगी। सभापति महोदय, हम तो यह बिल राज्य सभा में लेकर आए थे, मगर कांग्रेस पार्टी और कुछ दलों ने इस का विरोध किया ..(व्यवधान)..

श्री बी0के0 हरिप्रसाद : हम ने विरोध नहीं किया। हमने उस में संशोधन करने के लिए कहा।

MR. CHAIRMAN: Mr. Hariprasad, please sit down.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) : कांग्रेस ने विरोध किया था।

श्री सभापति : रामदास जी, आप मंत्री हैं।

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह : सभापति महोदय, मैंने सदन में ' विरोध ' शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि विरोध का तरीका बदलने से विरोध बंद नहीं हो जाता है। आपने विरोध का तरीका अलग चुना है। आप यह मत मानिए कि जनता यह समझती नहीं है। वह सब कुछ जानती है। जब आप चुनाव में जाएंगे तो कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग के लोगों को जवाब देना पड़ेगा, देश के ओ0बी0सी0 वर्ग को जवाब देना पड़ेगा कि उसने इनके सम्मान की इस बात को क्यों रोका? सभापति महोदय, पूरा देश देख रहा है। मैं तो आज भी सारी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद के नाते अपील करना चाहता हूं कि इस बिल में कोई राजनीति नहीं है बल्कि पिछड़े वर्ग को सम्मान दिलाने की बात है। इसलिए आइए हम सब साथ मिलकर इस बिल को पास करें।

(1 पी/एएससी पर जारी)